

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 464] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 1972/कार्तिक 2, 1894

No. 464] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 1972/KARTIKA 2, 1894

[इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रसंग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th October 1972

S.O. 679(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Apollo Mills Ltd., Bombay, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Maharashtra State Textile Corporation, (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Apollo Mills Ltd., Bombay, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this notified Order.
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/43/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1972

का० 10 679(अ)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि अपोलो मिल्स लिमिटेड, बम्बई, औद्योगिक उपक्रम का जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विमिनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया जा चुका है, प्रबन्ध इस रीति से किया जा रहा है कि लोक हित में अति अहितकर है:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य बस्व निगम लि०, को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त उपक्रम, अर्थात् अपोलो मिल्स लिमिटेड, बम्बई, का पूर्ण प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए सभी निदेशों का पालन करेगा।
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदामीन रहेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, पहले ही समाप्त कर सकेगी।

यह आदेश गामकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांचवर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

[सं० एफ० 3/43/72-सी०यू०सी०]

के० एम० भटनागर, संयुक्त सचिव।